हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 2 मार्च 2026, समय 1810 (10 मिनट)

मुख्य समाचार :-

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री आज वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2 लाख 23 हजार 658 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया।

बजट में राजकोषीय घाटा 40,293 करोड़ 17 लाख रुपए दर्शाया गया । विभागों को पिछले बजट के मुकाबले अधिक बजट आवंटित किया गया।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2047 तक राज्य को एक ट्रिल्यन डॉलर की अर्थव्ययवस्था बनाने का लक्ष्य दोहराया।

धान छोड़कर दाले, तिलहन व कपास उगाने वाले किसानों को 2 हज़ार रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा।

*******

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री आज वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2 लाख 23 हजार 658 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। जो वित्त वर्ष 2025-26 के 2 लाख 2 हजार 816 करोड़ रुपए से अधिक के संशोधित आंकड़े से 10.28 प्रतिशत अधिक है।
मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा -

बजट में राजकोषीय घाटा 40,293 करोड़ 17 लाख रुपए का है जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.65 प्रतिशत है जबकि राजस्व घाटा 0.87 प्रतिशत और

प्रभावी राजस्व घाटा 0.41 प्रतिशत है। इसी तरह पूंजीगत व्यय 1.86 प्रतिशत, और प्रभावी पूंजीगत व्यय 2.32 प्रतिशत बताया गया है। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आवंटित राशि को 4.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 4,609 करोड़ 88 लाख रुपए, बागवानी विभाग की आवंटित राशि को 0.86 प्रतिशत से बढ़ाकर 1,176 करोड़ 91 लाख रुपए , पशुपालन एवं डेयरी विभाग की आवंटित राशि को 23.31 प्रतिशत से बढाकर 2,290 करोड़ 57 लाख रुपए, मत्स्य पालन विभाग की आवंटित राशि को 14.84 प्रतिशत से बढ़ाकर 242 करोड़ 41 लाख रुपए, सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि को 70.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 1,970 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।

इसी प्रकार सिंचाई क्षेत्र के लिए वर्ष 2026-27 के लिए 6,446 करोड़ 57 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

जन स्वास्थ्य विभाग के लिए 2025-26 के 5,469 करोड़ 22 लाख रुपए के संशोधित अनुमान के मुकाबले वर्ष 2026-27 में 5,912 करोड़ 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।

शिक्षा सहित मानव संसाधन विकास के लिए भी बजट बढ़ाया गया है, मौलिक शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को बढ़ाकर 10,855 करोड़ 48 लाख रुपए, सेकेंडरी शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 7,862 करोड़, 41 लाख उच्चतर शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को बढ़ाकर 4,197 करोड़ 38 लाख रुपए किया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और ईएसआई की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 11,507 करोड़ 11 लाख रुपए की तुलना में वर्ष 2026-27 में बढ़ाकर 14,007 करोड़ 29 लाख रुपए का

बजट आवंटित किया गया है। जो वर्ष 2025-26 के आवंटन से 32.89 प्रतिशत अधिक है

इसी तरह खेल एंव युवा सशक्तिकरण के लिए 2,200 करोड़ 63 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की आवंटित राशि को बढ़ाकर 1,950 करोड़ 92 लाख तथा श्रम विभाग की आवंटित राशि को बढ़ाकर 91 करोड़ 80 लाख किया गया है।
मुख्यमंत्री ने आबकारी एवं कराधान विभाग के लिए 77,950 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा है जो वर्ष 2025-26 के लक्ष्य से 13.24% अधिक है।

********

प्रस्तावित बजट में ऊर्जा विभाग के लिए 6,868 करोड़ रुपए और
लोक निर्माण (भवन व सड़कें) विभाग के लिए 5,893 करोड़ 66 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।

वहीं क्षेत्रीय परिवहन व यातायात विभाग के लिए वर्ष 2026-27 में बजट बढ़ा कर 3,542 करोड़ 79 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। नागरिक उड्डयन विभाग के लिए 573 करोड़ 34 लाख रुपए, पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग के लिए 8,703 करोड़ 75 लाख रुपए आवंतीती किए गए हैं।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग का बजट भी बढ़ा है, विभाग को इस बार
6,240 करोड़ 97 लाख रुपए मिलने प्रस्तावित हैं।

बजट में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को 556 करोड़ 61 लाख,
सभी के लिए आवास हेतु 2,424 करोड़ 39 लाख रुपए और
पर्यटन एवं विरासत विभाग के लिए 380 करोड़ 80 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।

पर्यावरण, वन्य जीव जंतु एवं प्राकृतिक संसाधन विभाग को

741 करोड़ 55 लाख, गृह विभाग को 8,475 करोड़ एक लाख रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बजट में राजस्व विभाग के लिए 19,500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.8% अधिक है। विभाग के लिए 4,024 करोड़ 28 लाख रुपए के बजट का प्रस्ताव किया गया है ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को 2,558 करोड़ 61 लाख,समाज कल्याण विभाग को 17,250 करोड 72 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 2,263 करोड़ 29 लाख रुपए रखे गए है।
बजट में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को 439 करोड़ 71 लाख रुपए,
कला एवं संस्कृति विभाग को 132 करोड़ रुपए देने और
खान एवं भू-विज्ञान को 164 करोड़ 16 लाख रुपये दिए जाने प्रस्तावित हैं।
विदेश सहयोग विभाग को 10 करोड़ 43 लाख रुपए,सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग को 178 करोड़ 14 लाख रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है।
बजट में नागरिक संसाधन सूचना विभाग के लिए 422 करोड़ 78 लाख रुपए रखे गए हैं।

*****

हरियाणा विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य को वर्ष 2047 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य दोहराया।

मुख्यमंत्री ने इसे जनभागीदारी से बना बजट" बताते हुए कहा-

मुख्यमंत्री ने हरियाणा साफ वायु परियोजना के लिए विश्व बैंक से 2,716 करोड़ की सहायता स्वीकृत होने की जानकारी दी. इस परियोजना के तहत वर्ष 2031 तक पीएम 2.5 सहित प्रमुख प्रदूषकों में बड़ी कमी का लक्ष्य रखा गया है.

इसके अलावा वॉटर सिक्योर हरियाणा परियोजना के लिए 5,715 करोड़ तथा हरियाणा ए आई मिशन के लिए 474 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। एआई मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और विभागीय सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल लागू किए जाएंगे।

बजट में कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। धान छोड़कर दालें, तिलहन व कपास उगाने वाले किसानों को 2,000 प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा. देसी कपास प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर 4,000 प्रति एकड़ की जाएगी। प्राकृतिक/जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमाणित किसानों को 10,000 प्रति एकड़ वार्षिक अनुदान मिलेगा। 8 लाख नलकूपों की गुणवत्ता जांच के लिए तीन वर्षीय योजना शुरू होगी।

*******************